सरकारी क्षेत्र में उद्योग

9. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में चलने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है उनमें अब तक कुल कितनी पूंजी लगी है तथा अब तक कितने का घाटा हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : अपेक्षित ब्यौरा 15 मार्च, 1985 को राज्य सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खण्ड I के अध्याय 2 और 16 में उपलब्ध है ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, कनाट प्लेस

10. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन के कनाट प्लेस बिक्री केन्द्र का रुपया कुछ लोगों पर बकाया था, जिसको बट्टे-खाते में डाल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गयी है और जिन पर यह राशि बकाया थी उनके नाम और पते क्या है और क्या वे उस राशि को देने की स्थिति में नहीं है अथवा उन पर वसूली के लिये कार्यवाही नहीं की जा सकती है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बन्द पड़े उद्योग

11. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के अब तक ऐसे कितने उद्योग हैं, जिन्हें बन्द कर दिया गया है या इस समय बन्द पड़े हुए हैं और उसके परिणाम स्वरूप सरकार को अब तक कितनी राशि का नुकसान हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : दो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों अर्थात्, केला तथा फल विकास निगम लिमिटेड और केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड या तो बन्द किये जा रहे हैं या बन्द पड़े हैं । 26.4.1982 तक केला और फल विकास निगम लिमिटेड ने 132.90 लाख रुपये की हानि उठाई थी । 17.6.1983 तक केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड ने अनन्तिम आधार पर 382.24 लाख रुपये की हानि उठाई थी ।

Introduction of Computer technique in the Supreme Court

12. SHRI ANSWANI KUMAR :
SHRI PYARELAL KHANDELWAL :

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether Government have examined the project submitted by Justice Lodha of Rajasthan High Court about introduction of computer technique in the functioning of the Supreme Court and for establishing an electronic centre to help in the speedy disposal of cases; and

(b) if so, what are the main features of the proposal and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) Justice G. M. Lodha had forwarded a copy of a monograph on the subject of computerisation. This was based on his study of computerisation in Judiciary in Europe, U.S.A. and Japan. It envisaged the introduction of computers in the Supreme Court and High Courts.